Publication	Mint	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Puja Das
Date	17/01/2024	Page no	11
CCM	68.14		

Govt, cooperatives move to set up world's largest granary

Govt, cooperatives move to set up world's largest granary

It is aimed at ensuring storage facilities for food grains and other agricultural goods

Puja Das
Puja.das@livemint.com
NEW DELHI

The ministry of cooperation plans to sign agreements with the key stakeholders involved in attempts to set up what the government calls the world's largest grain storage.

The pacts are planned to be signed with the Department of Consumer Affairs (DoCA), National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard), National Cooperative Development Corporation (NCDC) and National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd (NCCF), a senior official told *Mint*.

The move aims to integrate godowns built at the Primary Agricultural Credit Society (PACS) level with the national food grain supply chain, providing essential market linkages for PACS.

DoCA will permit NCCF to utilize its warehouses for storing various commodities like pulses, oilseeds, onions, and grains under various government schemes like the Price Support Scheme and Price Stabilisation Fund.

The move is aimed at ensuring adequate storage facilities for food grains and other agricultural commodities, the official said.

However, specifics regarding the amount of storage or the number of warehouses to be used remain unclear.

> Every year, the country loses 74 million tonnes of food grains, or 22% of its grain output, due to inadequate storage

This initiative is part of the government's strategy to address the shortage of food grain storage capacity in the country. Launched in May last year as a pilot project in various states and union territories, this plan is touted as the largest in the world in the cooperative sector.

At present, India has a grain storage capacity of about 145 million tonnes, with annual food grain output over 300 million tonnes. Every year, the country loses 74 million tonnes of food grains, or 22% of its grain output, due to inadequate storage.

Over the next five years, India is expected to expand storage capacity to 215 million tonnes.

Queries sent to the cooperation ministry, DoCA, NABARD, NCDC and NCCF remained unanswered.

To oversee this extensive plan, a National Level Coordination Committee comprising members from relevant ministries, departments and central government agencies has been established. The NLCC will guide the overall implementation and periodically review the progress.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Rajasthan Patrika	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	17/01/2024	Page no	4
CCM	31.54		

1625 cooperative societies will operate from the new office

नए कार्यालय से 1625 सहकारी समितियों का संचालन होगा

पत्रिका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली@ पत्रिका. गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को यहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सशक्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं।

देश में कुल 1625 बहु राज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत है और इनसे करोड़ों सदस्य जुड़े हुए, नए भवन से केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के सुचारु रूप से कार्य करने में सहायता मिलेगी।

मोदी सरकार में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को सशक्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। इनमें बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं नियमों का संशोधन, केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के 'डिजिटल पोर्टल' का शुभारंभ, बहु-राज्य सहकारी समितियों में निर्धारित समय पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कराने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' का गठन औरबहुराज्य सहकारी समितियों के लेखा परीक्षकों के लिए दो पेनल का गठन शामिल है।

साथ ही बहुराज्य सहकारी समितियों के लिये उपनियमों का टेपलेट बनाना, बहुराज्यीय सहकारी समितियों में सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करना, सीईएफ (सहकारी शिक्षा निधि) के बेहतर संग्रहण एवं निधियों के उपयोग एवं भुगतान सीआरसीएस पोर्टल बनाना, शिकायतों के निवारण के लिए'ओबड्समैन (लोकपाल)' के पद का सृजन, नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं मदद प्रदान करना और कार्यालय का पृथक प्रशासनिक ढांचा स्थापित करना जैसे कई कदम उठाए गए हैं।

देश में कुल 1625 बहु राज्यीय सहकारी समितियाँ पंजीकृत है और इनसे करोड़ों सदस्य जुड़े हुए हैं। केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए नए भवन का निर्माण किया गया है।नए भवन से केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के सुचारु रूप से कार्य करने में सहायता मिलेगी।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD